

प्रेषक,

डा० दिलबाग सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पचायतीराज एच ग्रा० अभि० सेवा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक/3 अप्रैल, 2009

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु बचनबद्ध मदों की धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 205/XXVII (1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय के अन्तर्गत कुल रु० 28767000.00 (रु० दो करोड़ सत्तासी लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित बचनबद्ध मानक मदों में व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	मानक मद	धनराशि (हजार रुपये में)
1	01- वेतन	20000
2	02- मजदूरी	183
3	03- मंहगाई भत्ता	4400
4	04- यात्रा व्यय	333
5	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	67
6	06- अन्य भत्ते	2200
7	08- कार्यालय व्यय	333
8	09- विद्युत देय	100
9	10- जलकर/जलप्रभार	33
10	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50
11	12- कार्या फर्नीचर एवं उपकरण	33
12	13- टेलीफोन परव्यय	100
13	14- कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/माटर गाडियों का क्रय	-
14	15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	333
15	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-
16	17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	167
17	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	167
18	42- अन्य व्यय	-
19	44- प्रशिक्षण व्यय	67
20	45- अवकाश यात्रा व्यय	67
21	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	67
22	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	67
	योग-03	28767

(रु० 28767000.00 रु० दो करोड़ सत्तासी लाख सड़सठ हजार मात्र)

3. छठें वेतन आयोग की सस्तुतियों के लागू होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश सामान्य भविष्य निधि खातों में नहीं डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सेवानिवृत्त होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कर्मिकों के सम्बन्ध में नहीं रहेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2009-01 में इससे पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना प्रत्येक विभाग द्वारा अलग से रखी जायेगी।

5. अप्रैल, 2009 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह "क", "ख", "ग" एवं "घ") की सूचना विभाग द्वारा रखी जायेगी, जिससे वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत विभागवार श्रेणीवार भरे जाने वाले पदों तथा इसके सापेक्ष होने वाले व्यय की जानकारी प्राप्त हो सके।

6. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेंजिंग करके कार्यदायी सरस्थाओं को अवमुक्त करायेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। जिन विभागों में यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन आदि में साख की व्यवस्था है, वहाँ पर साख की त्रैमासिक सीमा उसी प्रकार निर्धारित किया जाय, जैसा कि शासनादेश संख्या-ए-2-311/दस-98, दिनांक 29 जून, 1998 के प्रसतर-2(2) एवं 2(3) में निर्धारित है।

7. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि पुनर्विनियोग हेतु वित्त विभाग की सहमति अनुदान के अधीन दी जाती है, तब पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश पर वित्त विभाग द्वारा आदेश विशिष्ट पत्र संख्या का प्रयोग कर उसकी प्रति महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को उपलब्ध करायी जाय। वित्त विभाग को पुनर्विनियोग का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा-151 के अन्तर्गत प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त ही भेजा जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व पक्ष से पूजी पक्ष तथा पूजी पक्ष से राजस्व पक्ष में भी पुनर्विनियोग प्रतिबन्धित है।

8. जैसा कि बजट मैनुअल के पैरा -88 में इंगित किया गया है नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो का उत्तरदायी होगा कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी०एम०-14 पर नियमित रूप से वित्त विभाग को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी

जाय। बजट मैन्युअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9 वाह्य सहायतित परियोजनाओं अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सब प्लॉन के अन्तर्गत आवंटित परिध्वय के सापेक्ष बजट प्राविधान की स्वीकृतियों तत्परता से जारी कर दी जायें तथा किसी भी दशा में उक्त हेतु बजट में की गई व्यवस्था को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।

10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. वाहन क्रय तथा अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

13. अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसे फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तिकित करने में कठिनई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियों शासनादेश संख्या- बी-2-2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी बी0एम0-17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण-वितरण अधिकारी को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियाँ पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी किया जाये अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

14. प्रत्येक विभाग/अनुभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियाँ सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के अनुदान संख्या के

अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय -03 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी के अन्तर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(डा० दिलबाग सिंह)
सचिव।

संख्या //8 (1)/XII/2009/83(01)/2008-TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोनार्थ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(आर०पी० फुलोरिया)
संयुक्त सचिव।